

मई १९६१। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री. वी. नरसिम्ह राव की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण ब्रह्मजालि अपिष्ट की। इस मौके पर मोदी ने नरसिम्ह राव की जयंती पर उन्हें ब्रह्मजालि अपिष्ट करते हुए कहा कि उनके देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में भारत की प्रगति में स्वाधीन और उल्लेखनीय योगदान दिया। जानकारी के लिए बता दें कि राव का जन्म 28 जुन 1921 को हुआ था और उन्होंने 23 दिसम्बर 2014 को दुनिया छोड़ दी। 21 जुन 1991 से 26 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री. वी. नरसिम्ह राव की जी जयंती पर उन्हें ब्रह्मजालि अपिष्टे हमारे देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण सालझंडे में भारत की प्रगति में स्वाधीन योगदान

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 229 ● नई दिल्ली ● सोमवार 29 जून 2026 ● प्रभात कालीन

●मूल्य: 3 रूपया

रेपब्लिकन

मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail:

rmmdp@hotmail.com

अनापारिक्त गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी

विल्ली-८६

**ट्रम्प बोले- ईरान नहीं सुधरा तो
उसका अस्तित्व नहीं बचेगा**



अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमले किए; ईरान का बहरीन-कुवैत पर अटैक

तेल अवशेष। अमेरिकी राष्ट्रपति
खोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अफगानिस्तान
इस्यन नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व
नहीं बचेगा। दूरुघ मोशल पर पोसत
कर उठेने कल, लगत है इयान कल
नही सुधरेगा, लेकिन हम ओ समय
नही बरत पाहेंगे। एक समय ऐसा भी
आ सकता है जब ह्ये उस रीट
अधियम को पूरा करना पड़ेगा
जिसको शुरुआत हमने बहुत सफल
तरेके से की थी। अगर ऐसे हुआ तो
इस कल अस्तित्व ही नहीं बचेगा।

वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। CENTCOM के मुताबिक वे हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। दूसरीबाई 'एम/टी किंकु' नाम के तेल टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। दूसरी ओर, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस और बस्योन में अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।

न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा, न वोट, प्रयागराज में अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, चंदे से लेकर भ्रष्टाचार तक लगाए आरोप



प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राविकार को कहा कि इच्छा में केदारेश्वर शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन के लिए अपोछा जाएंगे। अखिलेश यहां संवाददाताओं को मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ को और से हल्ल में कौ नई उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री ने अखिलेश के अपोछा न जाने का जिक्र किया था। यादव ने कहा, इच्छा में केदारेश्वर शिव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन के लिए अपोछा जाऊंगा। लेकिन महा मेले दौरे का नहीं है।

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
उन्होंने मुख्यमंत्री को आलोचना करते
हए कहा. वह (मुख्यमंत्री) बार-बार

दावा करते थे कि वह कई बार
 अयोध्या गए हैं, फिर भी उन्हें इस
 बात की जानकारी नहीं थी कि वहां
 क्या हो रहा है। इससे गिरफ्तार
 अंधेरा वाली कहवात सच साबित
 होती है। यद्यपि वे दावा किया, अगर
 वह ऐसा हो सकता है, तो तहसीलों,
 पुलिस थानों और दूसरी जगहों पर
 घुमना का उस व्यक्ति को क्या
 अंदाजा लगाया जा सकता है।
 धर्म और राजनीति को लेकर
 बीजेपी पर हमला
 उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले
 एक दशक में केवल प्रयागराज में ही
 विकास कार्यों का आँट कर
 जाएँ तो बड़े पैमाने पर मजदूरों
 सामने आएँगे। यह दावा करते हुए
 कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

धर्म का इस्तेमाल एक आइड के रूप में कर रही है, यादव ने कहा, समाजवादी लोग चाहते हैं कि समस्त धर्म को रखा जाए, लेकिन समस्त धर्म को आइड में पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। उन्होंने गेजमर, भर्ती, आरक्षण और घाघरचार के मुद्दे पर भाषणा सस्कार को पैदा साब हो प्राम मॉडर के चर्चे में कथित रेपफेरी के मामले का भी झूठे किया।

**स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर
उठाए सवाल**

यादव ने नौकरियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा, जब वे नौकरियों और रोजगार की बात करते हैं, तो उन्हें कम से कम अपने विभागों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अगर हम आगरा, गोरखपुर और अन्य जगहों के अंकड़ों को देखें,

अपने गिरेबान में झाँके
पाकिस्तान, कराची
आतंकी हमले के आरोप
पर भारत ने इस्लामाबाद
को दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। भारत ने कराची में हाल ही में हुए विस्फोट को लेकर पाकिस्तान को ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को लगाए गए आरोपों के अंदर झूठों की भी उम्मीद दायी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कराची की घटना को लेकर पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ़ उन्होंने के बनाए पाकिस्तान को अपने भीतर झूठों का चोरी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि उसे अपनी सरजमीं पर मौजूद आतंकी चंचे के खिलाफ विधायनी कार्यवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकीकरण से राय की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी प्रवृत्ति भी छोड़नी चाहिए। कराची स्थल में सिंधू रेंजर्स के एक कैप्टन पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सेना की मोर्चाबंदी शाखा आईएसपीआर ने इस हमले के लिए भारत को निम्नोद्देश्य बताया था पाकिस्तान ने हत्याएं प्रतिबंधित संगठन जमात-उल-अहरार के भारतीय समर्थित संगठन बनते हुए झूठे आरोप लगाए थे। यही नहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आरोप लगाया कि भारत पूरे क्षेत्र में ऐसे मुक्तों के बख़्ख़ दे रहा है, जो उसको संग्राम में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं।

भारत विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर- ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया; कप्तान हरमनप्रीत की फिफ्टी काम नहीं आई

लंदन। भारतीय विमेष टीम टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। लॉर्ड्स में खेले गए क्रो या ग्रे भूकाले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने 171 रन का टारगेट बना था, लेकिन एर्लिस पेरेरा और एस्ते गाईडर की शतकीय साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया। 36 नमन हयन-प्रोक्त कैर की 27 गेंदों में 56 रन की पायी टीम को जीत नग्न दिला सकी। इस हार के साथ भारत कम्प-ए में तीसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया। टीएस जॉन्कर पहले बल्लेबाजी करने वाले

भारत को शेफाली वामा और स्मृति मंधाना ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले क्रिकेट के लिए 66 रन जोड़े। शेफाली ने 26 गेंदों में 34 रन बनाए। स्मृति ने 37 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन बनाए। इसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। शेफाली गेंडियुम (34 रन) के साथ तीसरे क्रिकेट के लिए 64 रन जोड़कर उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आखिरी ओवर में सोफी मॉर्निन्गु पर लगातार तीन छक्के लगाकर हरमनप्रीत ने भारत का स्कोर 170 रन तक पहुंचा दिया। 171 रन



का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मुकदमा अखी नहीं छोड़े। रेफुका सिंह ने दूसरी ही पंथ पर जातीय विल का LBW कर भारत को फाली सफलता दिलाई। इसके बाद श्री चरण ने फिनीं लिफोर्ड और टोमि सामां ने बेथ मुनी को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 68/3 पर पहुंचा दिया।

अस समय भारत मुकाबले में मजबूत स्थिति में दिखा रहा था। तीन विकेट गिरने के बाद एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने भारतीय मैदानों पर दबाव बना दिया। दोनों ने चौथे विकेट का हथिया 57 गेंदों में 100 रन की पैर जितकर साझेदारी की। पेरी ने 38 गेंदों में 56 रन बनाए। गार्डनर 29 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहें।

ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। एवियर को फाले मुकाबले में साथ अफ्रीका ने बोल्लोदेश को हरकर 8 अंक हासिल कर लिए थे। ऐसे में भारत को अंतिम-4 में जगह बनाने के लिए हर खेल में जीत चाहिए थी। हर के साथ भारत 5 मैचों में 6 अंकों के साथ फाय-ए में तीसरे स्थान पर रहा।

ऑस्ट्रेलिया ने 10 अंक और साथ अफ्रीका ने 8 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई।

में 56 रन बनाए। गांडेन 29 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहें। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। एवेंबर्ग को पहले मुकाबले में साठवें अफ्रीकाने ने बॉल्लादेश को हरकर 8 अंक हासिल कर लिए थे। ऐसे में भारत को अंतिम-4 में जगह बनाने के लिए हर खेल में जीत चाहिए थी। हर के साथ भारत 5 मैचों में 6 अंकों के साथ फायर में तीसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 10 अंक और साठवें अफ्रीकाने ने 8 अंक के साथ सेमीफाइनल्स में जगह बनाई।





भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के

राष्ट्र अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे जी को

कर्नाटक से दूसरी बार

राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ



श्री सुरेन्द्र कुमार
उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश



निवेदक: किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी



विजय कुमार भारती
पत्रकार, महासचिव: किराड़ी जिला

रिपब्लिकन मजदूर संगठन

सम्पादकीय...

बांग्लादेश की विदेश नीति

बांग्लादेश के ज्वनिलिखित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने कार्यकाल की शुरुआत जिस प्रकार की विदेश नीति से की है, उसने दक्षिण एशिया की कूटनीति में नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश टर के लिए भारत या चीन में से किसी एक देश को चुनते रहे हैं, लेकिन तारिक रहमान ने सबसे पहले मलेशिया और उसके बाद चीन की यात्रा कर यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करना चाहती है। विशेष रूप से चीन की यात्रा और वहां हुए समझौते ने यह संकेत दिया है कि छका अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव कर रहा है। यह परिवर्तन केवल बांग्लादेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। चीन यात्रा के दौरान तारिक रहमान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक सहयोग से जुड़े कई समझौतों पर सहमति बनी। सबसे अधिक नया आर्थिक क्षेत्र (इकोनॉमिक जोन) को लेकर हुई, जिसे मोगला बंदरगाह के पास विकसित किया जाएगा। ठेकेदारों ने कि यहाँ परियोजना पहले भारत के सहयोग से प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर चीन के साथ नया समझौता किया गया। इस निर्णय को बांग्लादेश की बदलती विदेश नीति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। मोगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यह न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बांग्ला की खाड़ी में सामरिक महत्व भी रखता है। चीन यदि यहाँ औद्योगिक और आर्थिक निवेश बढ़ाते हैं तो उसे दक्षिण एशिया में अपनी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह चीन की बेल्ट एंड रोड प्लान की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा माना जा सकता है, जिसके माध्यम से वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है। भारत के लिए यह घटनाक्रम निता का विषय माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले डेढ़ दशक में काफी मजबूत हुए थे। सीमा समझौते, ऊर्जा सहयोग, सड़क और रेल संपर्क, जलमार्ग, सुरक्षा सहयोग तथा व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमीन के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को दक्षिण एशिया की सबसे सफल द्विपक्षीय साझेदारियों में गिना जाता था। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ दूरी दिखाई देने लगी है। तारिक रहमान की सरकार का चीन की ओर झुकाव इस बात का संकेत हो सकता है कि छका अब विदेश नीति में संतुलन बनाने के बजाय अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। चीन बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर निवेश, अमाना ज्ञा और आधारभूत संरचना परियोजनाओं का प्रस्ताव दे रहा है। ऐसे में आर्थिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए बांग्लादेश के लिए चीन एक आकर्षक साझेदार बनकर उभर रहा है। हालांकि चीन के निवेश के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। श्रीलंका के हम्बरटोटो बंदरगाह का उद्घाटन अवसर दिया जाता है, जहाँ ज्ञा भूतान में कटिनाइयों के कारण बंदरगाह का संचालन लंबे समय के लिए चीन को सौंपना पड़ा। इसलिए बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक सहयोग उसकी वितीय स्थिरता और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो तथा वह अत्यधिक ज्ञा निर्भरता का शिकार न बने। भारत के दृष्टिकोण से भी यह समय अपनी पड़ोसी नीति की समीक्षा का है। यदि बांग्लादेश चीन के साथ अपने संबंध मजबूत करता है तो भारत को केवल सामरिक प्रतिस्पर्धा के बजाय सकारात्मक कूटनीति पर ध्यान देना होगा। व्यापार, निवेश, रणक परियोजनाओं, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाकर ही भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी के साथ विश्वास बनाए रख सकता है। केवल सुरक्षा के नजरिए से संबंधों को देखने के बजाय आर्थिक साझेदारी को भी समान महत्व देना होगा। दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी उसका निवेश बढ़ना भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकता है। हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बांग्लादेश भारत से दूरी बनाम चाहता है। संभव है कि छका दोनों बड़े शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीति अपना रहा हो। आज अफिरका छोटें और मध्यम आकार के देश योी रणनीति अपनाते हैं। तारिक रहमान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक कूटनीति का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। विकासशील देशों के लिए निवेश, उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य बनते जा रहे हैं। यदि चीन इन क्षेत्रों में आर्थिक अवसर प्रदान करता है, तो स्वाभाविक रूप से कई देश उसकी ओर आकर्षित होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बहुत गहरे हैं। दोनों देशों की साझा सीमाएँ, भाषाई और सांस्कृतिक निकटता तथा 1971 के मुक्ति संग्राम का इतिहास इस संबंधों को विशेष बनाता है। इसलिए, किसी भी संभाव्यी राजनीतिक परिवर्तन को स्थायी दृष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के लिए सहयोग हो सबसे लाभकारी विकल्प रहेगा। अंततः तारिक रहमान की चीन यात्रा केवल एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का संकेत है। यह दिखाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में आर्थिक हित, निवेश और रणनीतिक साझेदारियाँ अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ विश्वास, विकास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित संबंधों को और मजबूत करे। वहाँ बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक विकास को समीच प्राथमिकता दे।

चढ़ावा चोरी पर ‘राजनीति’

अयोध्या के श्री राम मन्दिर में चढ़ावा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह त्वरित कार्रवाई करके इस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आठ कर्मचारियों के खिलाफ नामजद पुलिस रिपोर्ट करके उन्हें गिरफ्तार कराया है उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था के विरुद्ध किये गये कृत्य से अहत है और वह हर कीमत पर दोषियों को सजा देना चाहती है। अतः इस चढ़ावा चोरी को लेकर राय में राजनीतिक दल 2027 के आसन्न विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो आरोप लगा रहे हैं वे बन्द होने चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान राम के प्रति श्रद्धा का मामला कोई राजनीतिक विषय नहीं है बल्कि यह विशुद्ध रूप से धार्मिक व आस्था का प्रश्न है। योगी सरकार ने जिस तरह आरोप लगते ही पूरे मामले की जांच के लिए जिस तरह उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया उसकी भी विपक्षी राजनीतिक दल विशेष रूप से सम्मानजदी पार्टी आलोचना कर रही है मगर वह यह भूलें जा रहें है कि जब नम्बे के दशक में अयोध्या में रामप्रक मन्दिर बनाये जाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे और वह मांग कर रहे थे कि रामजन्म भूमि जन्म स्थल पर 16वीं सदी में खड़ी की गई बाबरी मस्जिद हटाई जाये तो इसी पार्टी के मुखिया स्व. मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर गोलीयाँ चलवाई थीं और कई रामप्रको को शहीद कर दिया था। अतः इस पार्टी के वर्तमान मुखिया श्री अखिलेश यादव का अब चढ़ावा चोरी के मामले में बहु-चढ़ कर आरोप लगाना विशुद्ध राजनीति से प्रेरित है और इसमें वह एक अवसर की तलाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिन्दुओं के धार्मिक स्थल पर चढ़े चढ़ावे में घपला करने के आरोप पहली बार लगे हैं। इससे पूर्व दक्षिण भारत के कई प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थों में इसी प्रकार का घपला किये जाने के आरोप लगते रहे हैं जिसकी जांच बकायदा कानूनी दायरे में होती रही है। परन्तु अयोध्या का श्रीराम मन्दिर भारत की जनता



द्वारा लगातार पांच सौ वर्षों से अधिक तक किये गये संघर्ष का प्रतीक है अतः यह मामला अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है जो कि पूरी तरह उचित व तार्किक है। इसीलिए राय के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया है कि कुछ लोग रामप्रको की अग्नि परीक्षा न लें और अनर्गल आरोप लगाना बन्द करें जिनके पास घपले के सन्दर्भ में कोई प्रमाण या साक्ष्य है वे विशेष जांच दल को सौंपें। योगी आदित्यनाथ ने आरोपों के लगते ही यह घोषणा की इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी लेकर रहेगा और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। अतः इसी क्रम में राम मन्दिर ट्रस्ट के आठ कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में वह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ट्रस्ट एक स्वायत्तशासी स्वतन्त्र संस्थान है जिसके कार्य में सरकार का कोई दखल नहीं है। इस ट्रस्ट को 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्म स्थान के पक्ष में फैसला दिये जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा गठित किया गया था जिसने मन्दिर का निर्माण करने के बाद इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उठाई अतः अब यह

ट्रस्ट की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह खुद को پاک-साफ दिखाये। इस सिलसिले में ट्रस्ट के महासचिव श्री चम्पतराय व इसके कोष के कर्तव्यार्थी अनिल मिश्रा के इस्तीफा देने की खबरें भी आ रही हैं। अतः यह साफ है कि ट्रस्ट में नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेने की भावना जागृत हो रही है और वह चाहता है कि जांच का काम पूरी शुद्धता के साथ पूरा हो। चूंकि यह मामला विश्व के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए राजनीतिक दल इसे अपने लाभ के अवसर में बदलना चाहते हैं और बहु-चढ़कर आरोप लगा रहे हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को सचेत करना पड़ा कि जो लोग कल तक भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे थे और न्यायालयों में रामजन्म भूमि क्षेत्र के विरुद्ध कर पर तक प्रस्तुत कर रहे थे वे तो आज सबसे आगे बढ़कर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ श्री योगी आदित्यनाथ का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे ट्रस्ट की सफाई करने का सघन अभियान चलायें और इसे किसी भी प्रकार के सन्देह से ऊपर रखें क्योंकि जब धर्म व आस्था के केन्द्र में चोरी होती है तो पूरा मानव हृदय भीतर से चौत्कार करने लगता है और उसका विश्वास गहरे तक हिल जाता है। वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा की श्रेणी में भी आता है क्योंकि हर वर्ष का श्रद्धालु अपनी गाड़ी कमाई का एक अंश भगवान की अर्पण करके खुद को धन्य समझता है। उसका यह भाव स्वप्रेरित होता है क्योंकि जब एक गरीब मजदूर भी अपने आराध्य के मन्दिर में जाता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि वह भी ईश्वर को कुछ न कुछ जरूर चढ़ावे। अतः इस चढ़ावे में यदि चोरी होती है तो उसका पछाताप भी स्वीकार्य नहीं होता। परन्तु चढ़ावा चोरी मनुष्य की उस मौलिक धन लिप्ता का भी प्रतीक है जो उसे ऐसा कृत्य करने के लिए उकसाती है अतः पूरे समाज के लिए भी यह स्थिति शोचनीय है।

सूडान गृहयुद्ध में भारतीय कड़ी पर अमेरिकी प्रतिबंध

भारतीय कंपनियाँ खनन, आधारभूत ढांचे, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों के लिए विस्फोटक सामग्री का उत्पादन करती हैं और कई देशों को निर्यात भी करती हैं। ऐसे में निर्यात नियंत्रण, अंतिम उपयोगकर्ता की पहचान तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी उत्पाद का उपयोग तीसरे पक्ष द्वारा संघर्ष क्षेत्रों में किया जाता है, तो उससे निर्माता कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है, भले ही उसकी प्रत्यक्ष भूमिका सिद्ध न हुई हो। यह मामला भारत के लिए इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि देश स्वयं जिम्मेदार रक्षा निर्यातक की छवि बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ऐसे समय में किसी भारतीय नागरिक या कंपनी पर विदेशी प्रतिबंध लगना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त सावधानी और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव केवल संबंधित व्यक्ति या कंपनी तक सीमित नहीं रहता। ऐसे प्रतिबंधों के बाद अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, डॉलर आधारित लेन-देन, वैश्विक व्यापारिक साझेदारियाँ और विदेशी निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं।

अफ्रीकी देश सूडान में जारी गृहयुद्ध अब केवल स्थानीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, हथियारों के कारोबार और वैश्विक कूटनीति का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इसी क्रम में अमेरिका ने सूडान के संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए आठ व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें एक भारतीय नागरिक और छठीसगढ़ स्थित एक विस्फोटक (एक्सप्लोसिव) निर्माण कंपनी का नाम भी शामिल है। यह घटनाक्रम भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न केवल उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है, बल्कि रक्षा और औद्योगिक निर्यात से जुड़े नियामक ढांचे पर भी संकल खड़े हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार निव व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे कथित तौर पर ऐसे सरीद (प्रोविनोरमेंट) और भर्ती (रिक्लूटमेंट) नेटवर्क का हिस्सा थे, जिन्होंने सूडान में युद्धरत पक्षों तक संसाधन, उपकरण या अन्य सहायता पहुंचाने में भूमिका निभाई। अमेरिका का दावा है कि इन नेटवर्कों ने संघर्ष को और अधिक लंबा तथा हिंसक बनाया है। हालांकि प्रतिबंध लगना किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होना नहीं है, बल्कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपनी विदेश नीति और विश्वास सुरक्षा कानूनों के तहत उठाया गया एक प्रशासनिक कदम है। सूडान अप्रैल 2023 से भीषण गृहयुद्ध की चपेट में है। सेना और अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सों के बीच सत्ता संघर्ष ने पूरे देश को हिंसा, विस्थापन और मानवीय संकट में धकेल दिया है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने की मजबूर हुए हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र लगातार चेतावनी देता रहा है कि बाहरी देशों और इनैरी नेटवर्कों से मिलने वाली सैन्य एवं वित्तीय सहायता इस संघर्ष को और अधिक जटिल बना रही है। इसी संदर्भ में अमेरिका ने उन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों पर कार्रवाई शुरू की है जो कथित रूप से युद्धरत गुटों तक हथियार, विस्फोटक सामग्री, वित्तीय संसाधन या अन्य सहायता पहुंचा रहे हैं।

अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यदि इन आपूर्ति शृंखलाओं को रोकना जाए तो संघर्ष को तीव्रता कम की जा सकती है और शांति वार्ता को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय नागरिक और छठीसगढ़ की कंपनी का नाम सामने आने से स्वाभाविक रूप से कई सवाल उठें हैं। क्या वास्तव में इनका किसी अवैध नेटवर्क से संबंध था? क्या निर्यात अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हुआ था या फिर उत्पाद किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिका ने अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक होगी। भारत का रक्षा और औद्योगिक विस्फोटक उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। भारतीय कंपनियाँ खनन, आधारभूत ढांचे, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों के लिए विस्फोटक सामग्री का उत्पादन करती हैं और कई देशों को निर्यात भी करती हैं। ऐसे में निर्यात नियंत्रण, अंतिम उपयोगकर्ता की पहचान तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी उत्पाद का उपयोग तीसरे पक्ष द्वारा संघर्ष क्षेत्रों में किया जाता है, तो उससे निर्माता कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है, भले ही उसकी प्रत्यक्ष भूमिका सिद्ध न हुई हो। यह मामला भारत के लिए इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि देश स्वयं जिम्मेदार रक्षा निर्यातक की छवि बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ऐसे समय में किसी भारतीय नागरिक या कंपनी पर विदेशी प्रतिबंध लगना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त सावधानी और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का प्रभाव केवल संबंधित व्यक्ति या कंपनी तक सीमित नहीं रहता। ऐसे प्रतिबंधों के बाद अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, डॉलर आधारित लेन-देन, वैश्विक व्यापारिक साझेदारियाँ और विदेशी निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ कारोबार

करने से बचती हैं ताकि वे स्वयं किसी कानूनी या वित्तीय जोखिम में न पड़ें। इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई का आर्थिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। दूसरी ओर वह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं होते। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और आरोपों का खंडन करने का अवसर मिलना चाहिए। यदि भारतीय नागरिक या कंपनी इन आरोपों को अस्वीकार करती है, तो जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती। इसलिए इस मामले को तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर देखना अधिक उचित होगा। यह घटनाक्रम वैश्विक हथियार और विस्फोटक व्यापार की निकलताओं की भी सामने लाता है। आज कई बार उत्पाद एक देश में बनते हैं, दूसरे देश के माध्यम से निर्यात होते हैं और अंततः किसी तीसरे देश के संघर्ष क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपूर्ति शृंखला की निगरानी, निर्यात नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपने निर्यात नियंत्रण तंत्र को और मजबूत बनाए, संवेदनशील वस्तुओं की निगरानी बढ़ाए तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन को और प्रभावी बनाए। इसमें न केवल भारतीय कंपनियों की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि भारत की जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि भी और मजबूत होगी। अंततः सूडान का गृहयुद्ध केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि आधुनिक संघर्षों में हथियारों, वित्तीय नेटवर्कों और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों में भारतीय नामों का शामिल होना भारत के लिए संतर्क रहने का संकेत है। आज वाले समय में जांच के निष्कर्ष के बाद तय करेंगे कि आरोप कितने सही हैं, लेकिन इनका स्पष्ट है कि वैश्विक व्यापार के इस दौर में पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

8वां वेतन आयोग- फिटमेंट फैक्टर पर टिकी

लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें

देश के लगभग 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी इन दिनों 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेमझी से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी फिटमेंट फैक्टर माना जा रही है, क्योंकि यही तय करेगा कि कर्मचारियों के मूल वेतन , पेंशन और कई भत्तों में कितनी वृद्धि होगी। विभिन्न संभावित फिटमेंट फैक्टर-2, 2.5 और 3-को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इनहीं के आधार पर संभावित वेतन वृद्धि के अंश-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिसके माध्यम से वर्तमान मूल वेतन को नए वेतन में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 निर्धारित किया जाता है, तो उसका संभावित मूल वेतन 50,000 रुपये हो जाएगा। इसीलिए वह केवल एक गणितीय सूत्र नहीं, बल्कि पूरे वेतन ढांचे की आधारशिला है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। कर्मचारी संगठनों की ओर से अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, जबकि सरकार को वित्तीय बोझ का भी ध्यान रखना होगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है, तो वेतन में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रहेगी। इससे कर्मचारियों को रहत हो मिलेगी, लेकिन बहुतों महंगाई और जीवन-खपान की लागत को देखते हुए कई कर्मचारी इसे अपर्याप्त मान सकते हैं। दूसरी ओर यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और इसे संतुलित विकल्प माना जा रहा है। वहीं यदि फिटमेंट फैक्टर 3 तक पहुंचता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में काफी बड़ी वृद्धि होगी, लेकिन इसमें केन्द्र सरकार के वेतन और पेंशन व्यय में भी भारी इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं रहता। यद्यपि छद्म रेट अलवेंस सीधे फिटमेंट फैक्टर से नहीं बढ़ता, लेकिन ग्रहणिक की गणना संशोधित मूल वेतन के आधार पर होती है, इसलिए मूल वेतन बढ़ने पर भी स्वतः बढ़ जाता है। इसी प्रकार कई अन्य भत्तों और पेंशन की गणना पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पेंशनभोगियों के लिए भी फिटमेंट फैक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। संशोधित मूल वेतन के आधार पर उनकी पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसलिए इसे वेतन आयोग की सिफारिशों केवल कर्मकर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को भी प्रभावित करेगा। हालांकि अंतिम निर्णय केवल कर्मचारियों की मांगों के आधार पर नहीं होगा। सरकार को राजकोषीय अनुशासन, आर्थिक विकास, महंगाई, कर संघर्ष और रखों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कई पहलुओं पर विचार करना होगा। यदि फिटमेंट फैक्टर बहुत अधिक रखा जाता है, तो वेतन, पेंशन, ग्रहण पेंशन प्रणाली तथा विनिष्कण्ड पेंशन स्कीम पर सरकारी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग को कर्मचारियों के हितों और सरकार की वित्तीय क्षमता के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि आयोग अपेक्षाकृत सकारणीपूर्ण रुख अपना सकता है, जबकि कर्मचारी संगठन अधिक उदार फिटमेंट फैक्टर को मांग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के बाद हो स्पष्ट होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलु महंगाई भत्ता है। जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत नियमित वृद्धि मिलती रहेगी।

सीलमपुर में नाबालिग की हत्या पर वीएचपी सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग

नई दिल्ली । तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय लकी कुमार की हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता जताई है। रविवार को वीएचपी के इंद्रप्रस्थ प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता गौतमपुरी इलाके में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। 24 जून को रात सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी में लकी कुमार पर चाकू से हमला किया गया। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की राजधानी में

इस तरह की घटना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। वीएचपी की ओर से मुख्य आरोपी फैजान और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की अपील की। गुप्ता ने कहा कि यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो आगे आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीएचपी का कहना है कि समाज इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की लड़ाई जारी रहेगी।

VB G RAM G कानून राज्यों पर डालेगा करोड़ों का अतिरिक्त बोझ? कांग्रेस ने सरकार को घेरा, उठाए कई सवाल

नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह 1 जुलाई से लागू किए जा रहे विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने नए कानून को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि नया कानून ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करेगा और रायों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। कांग्रेस ने दावा किया कि कई रायों ने भी इस नए कानून को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना व्यापक चर्चा और पर्याप्त परामर्श के मनरेगा को समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राय सरकारों और अन्य हितधारकों से इस विषय



पर गंभीर चर्चा नहीं की गई। जयराम रमेश ने कहा कि अब जब एक जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है, तब कई राज्यों ने इसके विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। जयराम रमेश के अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इस योजना के तहत रायों पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च को लेकर

चिंता व्यक्त की है। उनका दावा है कि इन राज्यों ने कहा है कि नए कानून से राय सरकारों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। कांग्रेस ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह राय मध्य प्रदेश ने भी इस योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि चार राय सरकारों ने योजना में कृषि के चरम सीजन के दौरान प्रस्तावित ब्लैकआउट अवधि

का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम और मजदूरी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कम से कम पांच रायों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग भी की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नए कानून से ग्रामीण श्रमिकों की मोलभाव करने की क्षमता कमजोर होगी। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा। यह दो दशक पुराने मनरेगा की जगह लेगा। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा संविधान से प्राप्त काम के अधिकार की गारंटी देता था, जबकि नया कानून केवल केंद्रीकरण और रायों पर वित्तीय दबाव बढ़ाने का काम करेगा।

पीएम पद की गरिमा को लेकर किरन रिजजू ने विपक्ष पर साधा निशाना



नई दिल्ली ।

मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू एक बार फिर विपक्ष पर हमलावर हैं। हालांकि उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए पीएम पद की गरिमा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने ब्रिटेन की संसद का एक वीडियो शेयर करते हुए भारत में भी उसी तरह का मॉडल अपनाने की मांग की है। किरन रिजजू ने रविवार (28 जून) को सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि हमें भी ब्रिटिश-वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र मॉडल को अपनाना चाहिए, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तानी मूल की महिला जो ब्रिटिश संसद है उनके द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें (जारा सुल्ताना) को संसद से बाहर जाने को बोल दिया। कैबिनेट मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में तो पीएम को कायर,

सरेंडर, आतंकवादी, चोर, गली के सड़क छाप कुत्ते और न जाने क्या-क्या कह देते हैं, तब भी किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उन्होंने आगे बताया कि अंग्रेजों ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल झूठ 'कहने पर ही पाकिस्तानी मूल की जारा सुल्ताना को संसद से बाहर फेंकवा दिया। पाकिस्तानी मूल की सांसद जारा सुल्ताना को ब्रिटिश संसद के स्पीकर लिंडसे होयेल ने संसद से बाहर कर दिया। बता दें कि जारा साल 2022 के बाद संसद से बाहर निकाले जाने वाली पहली सांसद हैं। जारा सुल्ताना के साथ ही सांसद ली एंडरसन को भी संसद से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तानी मूल की सुल्ताना ने पीटर मंडेलसन केस को लेकर संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठ बताते हुए कहा था कि उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। सुल्ताना ने जब असंसदीय शब्दों को वापस लेने से मना किया तो स्पीकर ने न सिर्फ उन्हें फटकार लगाई बल्कि संसद से बाहर कर दिया।

650 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई - पूर्व डीजीएचएस समेत दो लोग गिरफ्तार, सरकार ने सात कर्मियों को किया निलंबित

नई दिल्ली ।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने इस मामले में डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का मानना है कि दोनों की भूमिका कथित वित्तीय अनियमितताओं में महत्वपूर्ण हो सकती है। एसीबी इससे पहले सीपीए के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार कर चुकी है। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उधर, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के विभिन्न स्टोर्स में जांच के अनियमितताएं मिलने पर पांच फार्मासिस्टों और दो अधिकारियों को तत्काल से प्रभाव निलंबित कर

दिया है। सरकार का कहना है कि दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन में लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकारी व्यवस्था में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही अथवा अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह मामला केंद्रीय प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के माध्यम से दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए सर्जिकल सामग्री, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में

टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, बाजार दर से अधिक कीमतों पर खरीद, वास्तविक आवश्यकता के बिना सामान की खरीद, नियमों की अनदेखी तथा कुछ सप्लायर्स को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे आरोपों की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े वेंडरों समेत कई लोगों को पूछताछ कर रही है। सामने आ रहे तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों से अलग-अलग स्तर पर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी टेंडर मंजूरी, दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति, भुगतान, फाइलों के अनुमोदन और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने की पुष्टि होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

ट्रिब्यूनल ने कहा- सिर्फ शराब पीने से नहीं मानी जाएगी दुर्घटना में पीड़ित की लापरवाही, मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली । मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने कहा कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के केवल शराब पीने से ही लापरवाही साबित नहीं होती। पीठासीन अधिकारी शिरीष अग्रवाल ने 2018 में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को 30.77 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट (एमएलसी) में सचिन की सांस से

शराब की गंध आने का उल्लेख है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने तय सीमा से अधिक शराब पी रखी थी। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह नशे की हालत में वाहन चला रहे थे। पीठासीन अधिकारी शिरीष अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने तय सीमा के भीतर या उससे अधिक शराब भी पी हो, तब भी दूसरे वाहन

चालक को तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। केवल शराब पीना ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दुर्घटना में पीड़ित की भी लापरवाही थी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि सचिन तेज या लापरवाही से बाइक चला रहे थे या उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ट्रक चालक इस मामले में सबसे अहम

गवाह हो सकता था, लेकिन वह ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ। दुर्घटना ट्रक चालक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई। आदेश में कहा गया कि भले ही दोपहिया वाहन चलते समय हेलमेट न पहनना कानून का उल्लंघन है। इसी तरह दुर्घटना के समय ड्राइविंग लाइसेंस न होना भी इस मामले में पीड़ित की लापरवाही साबित नहीं करता।

यमुना के लिए समय निकालें, चिल्ला गांव में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने खुद संभाला सफाई का मोर्चा

नई दिल्ली । दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार लगातार यमुना घाटों पर सफाई अभियान चला रही है और लोगों को भागीदारी के लिए जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज रविवार को चिल्ला गांव पहुंचीं और यहाँ यमुना घाट सफाई अभियान में युवा स्वयंसेवकों, स्थानीय निवासियों और नागरिकों के साथ शामिल हुईं। इस संबंध में दिल्ली सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई का संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "दिल्ली सरकार वैज्ञानिक तरीकों, लगातार प्रयासों और जन-भागीदारी के जरिए यमुना को फिर से जीवंत करने के लिए प्रतिबद्ध है।" मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे यमुना के लिए कुछ समय निकालें और इस जन-आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनें। उल्लेखनीय है कि इससे पहले, दिल्ली सरकार ने 15 जून दिन रविवार को यमुना नदी सफाई अभियान 2026 के तहत 28 घाटों और अन्य जगहों पर सफाई अभियान चलाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी घाट पर सफाई अभियान का नेतृत्व किया था।

मन की बात में पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की उपलब्धियों की सराहना

दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निर्मित सी-295 विमान की पहली उड़ान का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश की कई उपलब्धियों को रविवार को रेखांकित करते हुए कहा कि इस विमान से देश की वैमानिकी निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि देश ने जून में विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि सी-295 विमान भारत में बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे 40 विमान यहीं भारत में बनाए जा रहे हैं और इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा वैमानिकी क्षेत्र को नयी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत में निर्मित पहले सी-295 सैन्य परिवहन विमान ने 10 जून को सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। भारतीय वायुसेना करीब 21,935 करोड़ रुपये की लागत से 56 सी-295 परिवहन विमान खरीद रही है। इनमें से 40



विमानों को टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा एयरबस के सहयोग से

वडोदरा स्थित निर्माण केंद्र में तैयार किया जाएगा। मोदी ने कहा कि जून

में देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं जो हर नागरिक को गर्व से भर देती हैं। उन्होंने कहा, हाल में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दूनागिरि, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 2,500 से अधिक स्थानों पर विभिन्न योग कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी काफी चर्चा रही जिसमें भारत ने 102 स्वर्ण पदक सहित कुल 114 पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किए जाने का भी उल्लेख किया।

भारत-सेशेल्स की दोस्ती- हिंद महासागर में मजबूत होगी पकड़, यूपीआई समेत 19 समझौतों का एलान

विक्टोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए रविवार को सेशेल्स ने 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' की मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह 34वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। सेशेल्स के राष्ट्रपति प्रदिप हर्मीनी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सेशेल्स की ओर से दिया जाने वाला यह अपनी तरह का पहला सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान प्राप्त करने के बाद इंटरनेट मौड़िया पर लिखा कि मुझे 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' सम्मान से सम्मानित करने के लिए सेशेल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति हर्मीनी का हृदय से आभारी हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ और इसे उन सभी देशों को समर्पित करता हूँ जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे हैं तथा पर्यावरण संरक्षण को आने वाली



पौढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। यह एक गंभीर चुनौती है, जिसका हमें मिलकर सामना करना होगा। मोदी ने कहा, भारत पृथ्वी को अधिक हरित बनाने के लिए हरसंभव योगदान देने को तैयार है। यह हमारा विभिन्न धर्म-जातियों, मिशन-लाइफ पर दिए जा रहे विशेष जोर, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों में हमारी सक्रिय भूमिका से स्पष्ट होता है। इस मौके पर राष्ट्रपति हर्मीनी ने कहा, 'यह

***पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान मिला।**
***भारत-सेशेल्स ने रक्षा, यूपीआई सहित 19 समझौते किए।**
***यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।**

सम्मान उन नेताओं व साझेदारों के प्रति हमारे राष्ट्र के गहरे सम्मान व कृतज्ञता का प्रतीक है, जिनके नेतृत्व एवं सहयोग ने हमारे ब्लू होराइजन के संरक्षक की भावना को साकार किया है।' विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह सम्मान प्रधानमंत्री को सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मिले सम्मानों की कड़ी में सबसे नवीनतम है। उन्हें इसके पहले खाद्य एवं कृषि संगठन

के एग्रीकोला मेडल, सियोल पीम प्राइज और संयुक्त राष्ट्र के 'चौथिन ऑफ द अर्थ' अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हर्मीनी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत और सेशेल्स ने रविवार को 19 महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की। इनके जरिये रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाएगा। ये समझौते हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेशेल्स के साथ सुरक्षा, संपर्क, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इनमें प्रत्यक्ष सौध, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग संबंधी समझौता, सेशेल्स में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का समझौता, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्सपोर्ट बैंक) के साथ एक व्यापक ऋण सुविधा समझौता तथा नए सेशेल्स

राष्ट्रीय अस्पताल की प्रारंभिक तैयारियों से संबंधित समझौता शामिल है। दोनों देशों ने सेशेल्स को एक तेज गति से बढ़ते देशों में देते, सेशेल्स रक्षा बल को 10 यूटिलिटी वाहन और पांच लेजर रेडियल श्रेणी की नौकाएं सौंपने, सेशेल्स कोस्ट गार्ड के पोत 'पीएस जेरोमेट' का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने तथा डोमिनियन विमान को आधुनिक प्लास कॉन्फिग प्रणाली से उन्नत करने की भी घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सुषमा स्वाजा विदेश सेवा संस्थान और सेशेल्स के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय के बीच राजनीतिक प्रशिक्षण, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, सेशेल्स के ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत नाविकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन की परस्परिक मान्यता, बाह्य अंतरिक्ष की खोज व उसके शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। सेशेल्स को छह एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सोमेट भी सौंपा गया।

एमपी-एमएलए से नहीं नापी जा सकती बालासाहेब की शिवसेना धाराशिव में बोले उद्धव ठाकरे- सारा रोजगार समेट कर ले गए गुजरात



धाराशिव। शिवसेना-यूटूटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज धाराशिव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर ज़रूर निशाना साधा। ठाकरे ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले से लेकर महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात भेजने के मुद्दे पर तीखे प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बालासाहेब की शिवसेना को चंद विपक्षियों और सांसदों की संख्या से नहीं मापी जा सकता। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे चंद की हेरफेरों के आरोपों को लेकर बड़ा दावा किया। ठाकरे ने कहा, इन लोगों ने प्रभु

श्री राम के मंदिर में भी चोरी की है। आज राम मंदिर के नाम पर सरेआम लूट मची हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले अब आस्था के सबसे बड़े केंद्र में भी भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
रोजगार को लेकर उद्धव ने क्या आरोप लगाए?
महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उछाल और ऑपरेशन टाइगर पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग शिवसेना को क्यों तोड़ रहे हैं? इनका असली मकसद शिवसेना, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र धर्म को पूरी तरह खत्म करना है। ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र में एक भी नया बड़ा उद्योग या कंपनी नहीं आई है। यहां आने वाले तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स और कंपनियां लगातार गुजरात भेजी जा रही हैं।
जनता सिखाएगी गहवारों को सबक- ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने बगावत करने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। असली शिवसेना आज भी जमीन पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अस्थिरता को चोट पहुंचाने वालों को राय की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में लोग अपने वोट को ताकत से महाराष्ट्र धर्म को खत्म करने की साजिश रचने वालों को करार जवाब देंगे।



**साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाए**

संत शिरोमणि

कबीर दास जी

की जयंती

पर शत-शत नमन



बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल खोजा आपना,
मुझसे बुरा न कोय।



विजय कुमार भारती
पत्रकार/राष्ट्रीय अध्यक्ष: आरएमएस



रिपब्लिकन मजदूर संगठन